

II. सकल मांग

कमजोर होते वृद्धि के आवेगों के दौर में कुल मांग की भूमिका 2008-09 में जननीति की प्रथम पंक्ति में आ गई। बाह्य मांग में तेज संकोचन - जैसा कि गिरते वैश्विक उत्पादन, रोजगार और विश्व व्यापार में गिरावट में परिलक्षित है - ने स्पष्ट रूप से भारत के निर्यात निष्पादन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में भारत के निवल निर्यातों (माल और सेवाएं) ने बढ़ता जा रहा घाटा दर्शाया। देशी मांग, निजी उपभोग और निवेश व्यय दोनों ही रूपों में, विशेषरूप से 2008-09 की तीसरी तिमाही से नरम पड़ गई। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मांग में संकोचन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकारी मांग में विस्तार करना जरूरी हो गया। वृद्धि में धीमेपन से उत्पन्न होनेवाले राजस्व पक्ष के दबावों के बावजूद, कर कटौतियों और अतिरिक्त व्यय के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की राशि जीडीपी का लगभग 2.9 प्रतिशत रही। परिणामस्वरूप वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित किए गए घाटे के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके और इस प्रकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्दिष्ट घाटा लक्ष्य और 2 वर्ष के लिए टाल दिए गए। कंपनी कार्य-निष्पादन लगातार कई वर्षों तक मजबूत रहने के बाद 2008-09 की तीसरी तिमाही में नरमी के संकेत दर्शाने लगा।

II.1 2008-09 के दौरान आर्थिक मंदी निवेश मांग में काफी कमी के साथ जुड़ी रही है जोकि हाल ही के वर्षों में वृद्धि की प्रमुख प्रेरक रही है। निजी उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग में उल्लेखनीय गिरावट थी तथापि, तीसरी तिमाही के दौरान शुरू किए गए निर्णायक राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कारण इसमें वृद्धि हुई। परिणामास्वरूप, केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण घाटा संकेतक अर्थात् राजस्व घाटा और 2008-09 के लिए संशोधित

अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के स्तर के साथ-साथ बीते वर्ष के स्तर दोनों से ही काफी अधिक था। लाभप्रदता के असर के साथ खासकर तीसरी तिमाही के दौरान विपरीत असर के साथ कार्पोरेट निष्पादन मंद बना रहा। जहां तक बाह्य मांग की बात है पण्य व्यापार घाटा 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) में तेजी से व्यापक हो गया क्योंकि अक्टूबर 2008 से निर्यात संकुचित हो गए। नवंबर 2008 से आयात भी संकुचित हो गया। तथापि, 2008-09 (अप्रैल - फरवरी) के दौरान आयात वृद्धि की तुलना में निर्यात वृद्धि में कमी होने में ज्यादा तेजी थी। 2007-08 में शिखर पर रहने के बाद बचत और निवेश दरों के 2008-09 में कम रहने की संभावना है जो आर्थिक वृद्धि में मंदी दर्शाता है।

देशी मांग

II.2 2008-09 के दौरान समग्र वृद्धि में कमी निजी उपभोग व्यय और निवेश दोनों में ही, विशेष रूप से वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान मंदी से प्रेरित थी।

वास्तविक सकल मीयादी निवेश की वृद्धि पिछली तिमाहियों में द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज करने के बाद तीसरी तिमाही में घटकर 5.3 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि में 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान तेजी आई जो छोटे वेतन आयोग भुगतान, कृषि ऋण माफी पर व्यय, तेल और उर्वरक सब्सिडियों और प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपायों को दर्शाती है (सारणी 9)।

II.3 भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार देशी उपभोग और देशी निवेश से प्रेरित है। हाल ही के वर्षों में एक ध्यान देने योग्य पहलू सकल मीयादी निवेश का योगदान रहा है। इसने वृद्धि की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा वहनीय बनाया है। 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान वास्तविक जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) का हिस्सा कम हुआ है जबकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) वास्तविक जीडीपी में सकल मीयादी निवेश का हिस्सा जो 2008-09 की

सारणी 9 : बाजार मूल्यों पर जीडीपी का विन्यास (आधार : 1999-2000) - वृद्धि दरें

मद	2007-08*	2008-09#	2007-08						2008-09		(प्रतिशत)	
			2007-08			2008-09			2007-08	2008-09		
			ति1	ति2	ति3	ति1	ति2	ति3	अप्रैल-दिसंबर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. कुल अंतिम खपत व्यय	8.3	8.2	6.6	7.8	8.0	7.6	7.0	7.8	7.5	7.5		
(i) निजी अंतिम खपत व्यय	8.5	6.8	8.4	7.5	8.9	7.7	6.9	5.4	8.3	6.6		
(ii) सरकारी अंतिम खपत व्यय	7.4	16.8	-2.4	10.0	2.0	7.1	7.9	24.6	2.7	13.3		
2. सकल अचल पूँजी निर्माण	12.9	8.9	12.9	16.2	13.7	10.1	15.1	5.3	14.3	10.1		
3. स्टॉक में परिवर्तन	51.7	36.9	54.1	51.7	52.2	-32.0	-32.0	31.2	52.7	-10.2		
4. बहूमूल्य वस्तुएं	2.7	-10.4	-8.0	1.4	16.5	29.2	22.9	-8.9	3.5	12.5		
5. निर्यात	2.1	20.8	-4.0	-4.8	6.1	23.2	10.6	11.4	-0.9	15.5		
6. आयात घटाकर	6.9	27.9	-0.7	-3.6	6.7	30.3	26.0	20.6	0.9	25.3		
1999-2000 मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	9.1	7.1	9.1	8.9	9.1	8.1	7.7	4.5	9.0	6.6		

* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

दूसरी तिमाही के दौरान शिखर पर था, वर्ष की तीसरी तिमाही में गिर गया (सारणी 10)।

सरकारी वित्त का मिश्रित बजट अनुमान : 2008-09

II.4 2008-09 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के मिश्रित वित्त पर इस आर्थिक मंदी का विपरीत प्रभाव पड़ा। इसने राजस्व वृद्धि को प्रभावित किया तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के संबंध में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता महसूस हुई। केंद्र सरकार के संबंध में वित्तीय स्थिति जैसी कि 2008-09 के संशोधित अनुमान में दर्शाई गई है, प्रमुख घाटा संकेतकों में दिखाई देने वाली वृद्धि प्रमुख घाटा संकेतकों में तेज वृद्धियां दर्शाती है (सारणी 11)। राज्य वित्त के संबंध में अनुमानित राजस्व अधिशेष निम्न राजस्व वृद्धि के कारण समाप्त हो जाने का अनुमान है। मिश्रित सकल राजकोषीय घाटा संकेतकों का वित्तपोषणस्वरूप बाजार उधारों के सतत वचस्व को दर्शाता है (चार्ट 4)।

केंद्र सरकार के वित्त 2008-09

II.5 वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्र सरकार के वित्त दबाव में आ गए। 2008-09 की पहली छमाही के दौरान वैश्विक पण्य मूल्यों (पेट्रोलियम उत्पादों सहित) में वृद्धि के कारण पैदा हुए मुद्रास्फीति दबावों के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए गए राजकोषीय उपाय जैसे कि कर में कटौतियां और बढ़ी हुई सब्सिडियों ने राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया। यह राजकोषीय तनाव 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान भी बना रहा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस वैश्विक वित्तीय संकट के प्रसारकारी प्रभाव की वजह से वृद्धि में गिरावट को रोकने की दृष्टि से कर कटौतियों और अतिरिक्त व्यय के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को लागू करने की आवश्यकता पड़ी (अनुबंध 1)। 2008-09 के दौरान इन उपायों का प्रभाव जीडीपी के 2.9 प्रतिशत के आसपास अनुमानित किया गया है।

सारणी 10 : बाजार मूल्यों पर जीडीपी का विन्यास (आधार : 1999-2000) - वृद्धि दरें

मद	2007-08*	2008-09#	2007-08			2008-09			2007-08	2008-09
			ति1	ति2	ति3	ति1	ति2	ति3	अप्रैल-दिसंबर	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1. कुल अंतिम खपत व्यय	66.9	67.6	70.4	67.2	67.4	70.1	66.8	69.5	68.3	68.8
(i) निजी अंतिम खपत व्यय	57.2	57.0	60.1	58.5	59.0	59.8	58.0	59.5	59.2	59.1
(ii) सरकारी अंतिम खपत व्यय	9.8	10.6	10.4	8.7	8.4	10.3	8.7	10.0	9.1	9.7
2. सकल अचल पूंजी निर्माण	31.6	32.1	31.7	33.0	30.8	32.3	35.3	31.0	31.8	32.8
3. स्टॉक में परिवर्तन	3.1	4.0	3.3	3.2	3.0	2.1	2.1	3.7	3.1	2.7
4. बहूमूल्य वस्तुएं	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.1	1.2	1.3
5. निर्यात	20.2	22.8	22.8	17.2	18.9	26.0	17.6	20.1	19.6	21.2
6. आयात घटाकर	24.6	29.4	23.6	24.2	24.0	28.4	28.3	27.7	23.9	28.1
7. विसंगतियां	1.5	1.8	-5.7	2.3	2.7	-3.3	5.1	2.1	-0.1	1.4

ज्ञापन: (करोड़ रुपए)

बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद	34,02,716	36,44,011	7,69,806	7,88,864	8,99,235	8,32,350	8,49,407	9,39,458	24,57,905	26,21,215
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

* : त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

सारणी 11: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)				
वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं*
1	2	3	4	5
केंद्र				
2007-08 सं.अ.	-0.9	1.1	2.7	60.1
2008-09 ब.अ.	-1.1	1.0	2.5	56.4
2008-09 सं.अ.	2.5	4.4	6.0	57.8
2009-10 ब.अ.	1.8	4.0	5.5	56.6
राज्य				
2007-08 सं.अ.	0.1	-0.5	2.3	28.3
2008-09 ब.अ.	0.1	-0.5	2.1	27.4
संयुक्त				
2007-08 सं.अ.	-0.3	0.9	5.2	76.7
2008-09 ब.अ.	-0.8	0.5	4.5	71.7

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

* : ऐतिहासिक विनिमय दरों पर बाह्य देयताएं शामिल

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

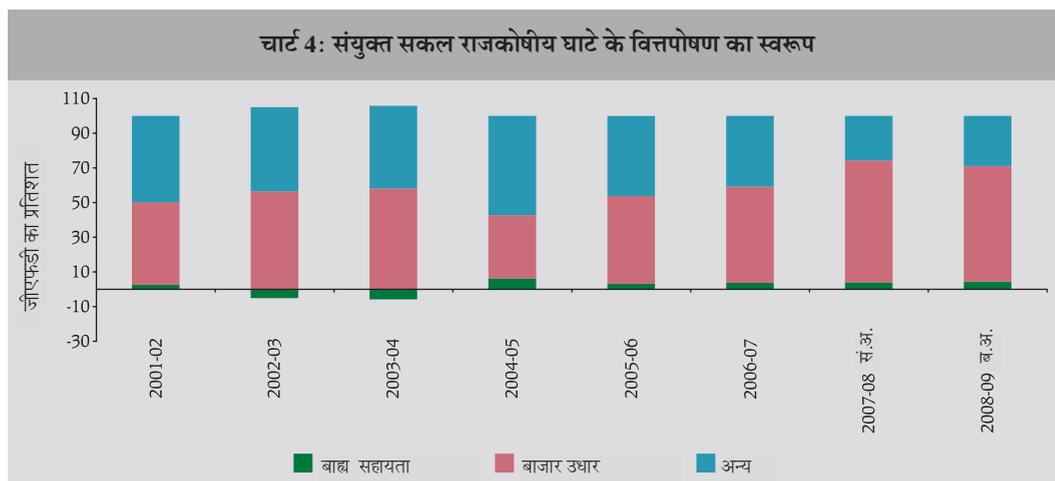
2. 2008-09 में जारी तेल/उर्वरक बॉन्ड का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत है।

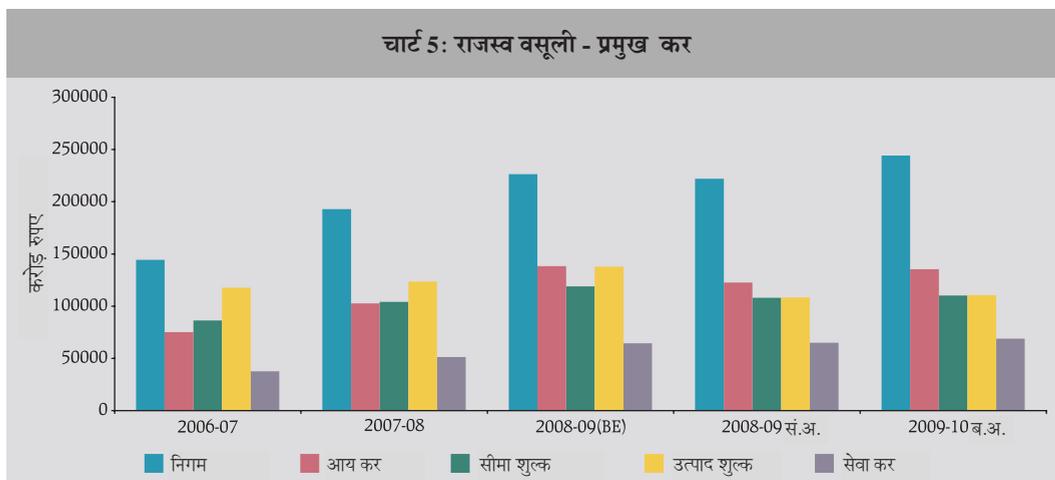
II.6 राजस्व प्राप्तियों में कमी के साथ जुड़ी व्यय की गैर आनुपातिक वृद्धि के कारण वर्ष 2008-09 के लिए राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक अर्थों के साथ-साथ जीडीपी के अनुपात के रूप में दोनों ही तरह से काफी ऊंचे रखे गये थे (देखें सारणी 11)। 2008-09 (सं. अ.) में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर राजस्व घाटा बजट अनुमानों की तुलना में 3.4 प्रतिशत

ऊंचा था। परिणामस्वरूप जीडीपी के सापेक्ष सकल राजकोषीय घाटा 2.5 प्रतिशत के बजट अनुमानों से बढ़कर 2008-09 (सं.अ.) में 6.0 प्रतिशत हो गया।

II.7 2008-09 के दौरान आर्थिक मंदी और कर दरों की कमी ने सकल कर राजस्व को प्रभावित किया जिससे केंद्र के निवल कर राजस्व और राज्यों को अंतरित किए गए कर राजस्व दोनों ही प्रभावित हुए। 2008-09 के

चार्ट 4: संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप





लिए संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व जो 6,27,959 करोड़ रुपए था, बजट अनुमानों की तुलना में 8.7 प्रतिशत कम था। सभी प्रमुख करों के अंतर्गत कर वसूली अपने बजट अनुमानों के स्तर से काफी कम थी (चार्ट 5)। 'अन्य करेतर राजस्व' जैसे कि आर्थिक सेवाएं, अन्य सामान्य सेवाएं तथा सहायता अनुदान और अंशदान

में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण बजट अनुमानों की तुलना में करेतर राजस्व मामूली रूप से अधिक था। तथापि, करेतर राजस्व यथा लाभांश और लाभ तथा ब्याज प्राप्तियों के प्रमुख घटकों में गिरावट आई। इसे दर्शाते हुए केंद्र की राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमानों की तुलना में कम रहने का अनुमान है (सारणी 12)।

सारणी 12 : केन्द्र सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)					
मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (व.अ.)	2008-09 (सं.अ.)	घट-बढ़ (4 पर 3)	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. कुल प्राप्तियां (2+3)	7,12,732 *	7,50,884	9,00,953	1,50,069	20.0
2. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	5,41,925	6,02,935	5,62,173	-40,762	-6.8
i) कर राजस्व (निवल)	4,39,547	5,07,150	4,65,970	-41,180	-8.1
ii) करेतर राजस्व	1,02,378	95,785	96,203	418	0.4
3. पूंजी प्राप्तियां	1,70,807	1,47,949	3,38,780	1,90,831	129.0
जिसमें से:					
बाजार उधार	1,30,600	99,000	2,66,539	1,67,539	169.2
ऋण की वसूली	5,100	4,497	9,698	5,201	115.7
विनिवेश आय	38,795 *	10,165	2,567	-7,598	-74.7

ब.अ. : बजट अनुमान

सं.अ. : संशोधित अनुमान

* : इसमें 34,309 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्टेट बैंक के स्टैक को भारत सरकार को अंतरित की गई है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

सारणी 13 :केन्द्र सरकार का समग्र व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)					
मद	2007-08 (लेखा)	2008-09 (ब.अ.)	2008-09 (सं.अ.)	घट-बढ़ (3 की तुलना में 4)	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. कुल व्यय (2+3=4+5)	7,12,732 *	7,50,884	9,00,953	1,50,069	20.0
	(15.1)	(13.8)	(16.6)		
2. योजनेतर व्यय	5,07,650 *	5,07,498	6,17,996	1,10,498	21.8
	(10.7)	(9.4)	(11.4)		
<i>जिसमें से:</i>					
व्याज भुगतान	1,71,030	1,90,807	1,92,694	1,887	1.0
	(3.6)	(3.5)	(3.6)		
रक्षा व्यय	91,681	1,05,600	1,14,600	9,000	8.5
	(1.9)	(1.9)	(2.1)		
आर्थिक सहायता	70,926	71,431	1,29,243	57,812	80.9
	(1.5)	(1.3)	(2.4)		
3. योजना व्यय	2,05,082	2,43,386	2,82,957	39,571	16.3
	(4.3)	(4.5)	(5.2)		
4. राजस्व व्यय	5,94,494	6,58,119	8,03,446	1,45,327	22.1
	(12.6)	(12.1)	(14.8)		
5. पूंजी व्यय	1,18,238 *	92,765	97,507	4,742	5.1
	(2.5)	(1.7)	(1.8)		

ब.अ.: बजट अनुमान

सं.अ.: संशोधित अनुमान

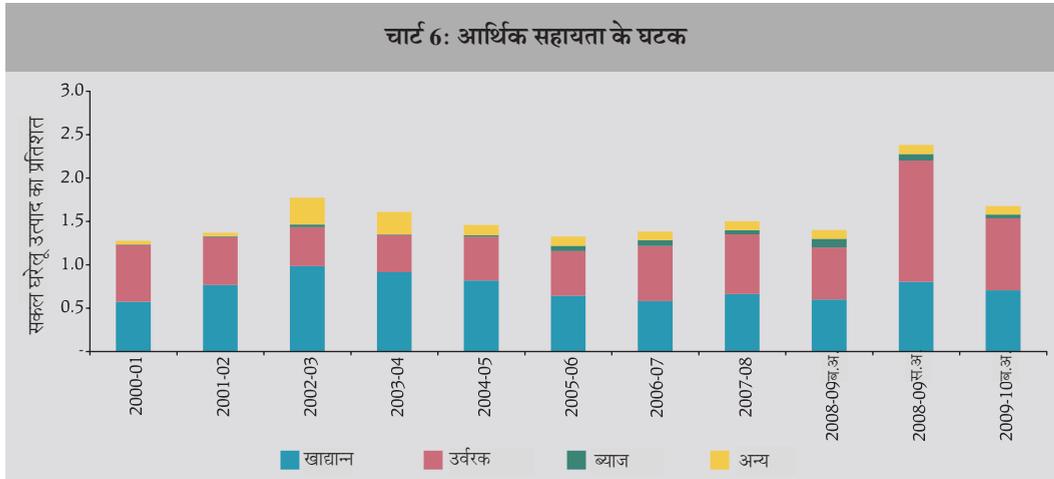
* : इसमें 35,531 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक का स्टेट बैंक के स्टेक के अधिग्रहण से संबंधित है।

II.8 2008-09 के लिए संशोधित अनुमानों में सकल व्यय अर्थव्यवस्था में समर्थनकारी सकल मांग को लक्ष्य करके किए गए राजकोषीय प्रोत्साहनपरक उपायों के कारण बजट अनुमानों की तुलना में अधिक था (सारणी 13 और अनुबंध 1)। राजस्व व्यय जिसका हिस्सा सकल व्यय की वृद्धि में 96.8 प्रतिशत था, मूल रूप से योजनेतर व्यय के अंतर्गत सब्सिडियों और रक्षा व्यय तथा योजना घटक के अंतर्गत ग्रामीण विकास के कारण था। 2008-09 के लिए संशोधित अनुमानों में सब्सिडियों पर होनेवाला व्यय 1,29,243 करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) था जो अनुमानित राशि से 80.9 प्रतिशत अधिक था। इसका मुख्य कारण खाद्यान्न और उर्वरकों पर दी जानेवाली सब्सिडियां थीं जो क्रमशः 10.960 करोड़ रुपए (33.6 प्रतिशत) और 44,863 करोड़ रुपए (144.8 प्रतिशत) थीं (चार्ट 6)। रक्षा राजस्व व्यय में वृद्धि रक्षा कार्मिकों के लिए छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने

के कारण थी। जहांतक पूंजी व्यय का संबंध है, एक ओर जहां रक्षा पूंजी परिव्यय में 7,007 करोड़ रुपए की गिरावट आई वहीं रक्षेतर पूंजी परिव्यय 5,790 करोड़ रुपए बढ़ गया।

केंद्र सरकार का वित्तपोषण

II.9 2008-09 के लिए केंद्र के सकल और निवल बाजार उधार (बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत आबंटनों को छोड़कर दिनांकित प्रतिभूतियां और 364-दिवसीय खजाना बिल) क्रमशः 1,78,575 करोड़ रुपए और 99,000 करोड़ रुपए थे। बजट अनुमानों के स्तर की तुलना में संशोधित अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटे में 2.4 गुना वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में निवल बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियां और 364-दिवसीय खजाना बिल) 2,66,539 करोड़ रुपए के बजटीय स्तर के 2.7 गुना बढ़ाए गए थे जिसने सकल राजकोषीय घाटे के 81.6



प्रतिशत का वित्तपोषण किया। बाजार उधारों के अलावा, अल्पावधि उधार (14-दिवसीय, 91-दिवसीय और 182-दिवसीय खजाना बिल) बजट अनुमानों के राजकोषीय घाटे के 10.5 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटे के 16.2 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे। लोक लेखे में जमाराशियां और अग्रिम तथा राज्य भविष्य निधियां संशोधित अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटे के क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगी। मुख्य रूप से अंतर्वाहों की तुलना में रेलवे निधियों के संबंध में बहिर्वाहों के अधिक होने के कारण आरक्षित निधियां 5.1 प्रतिशत का नकारात्मक योगदान देंगी।

बजट से इतर मदें

II.10 केंद्र सरकार बजट के माध्यम से खद्यान, उर्वरक और पेट्रोलियम पर स्पष्ट रूप से सब्सिडियां देने के अलावा विशेष बांडों के निर्गम के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ), उर्वरक कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों को सहायता प्रदान करती रही है। ये बांड राजकोषीय घाटा के प्रति तटस्थ माने जाते हैं क्योंकि इनमें कोई तत्काल नकद प्रवाह नहीं रहता है। अतः इन्हें बजटीय व्यय/प्राप्तियों

के अंग के रूप में नहीं माना जाता है। तथापि इन बांडों के राजकोषीय निहितार्थ हैं क्योंकि इनमें बाद की तारीख में चुकौती का दायित्व बना रहता है, अतएव इससे सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि होती है। इसके अलावा, ऐसे बांडों पर ब्याज की अदायगी राजस्व व्यय के एक अंग के रूप में मानी जाती है। वे राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार राजकोषीय घाटा प्रभावित होता है।

II.11 2008-09 के दौरान तेल विपणन कंपनियों और उर्वरक कंपनियों को क्रमशः 75,942 करोड़ रुपए तथा 20,000 करोड़ रुपए की राशि के विशेष बांड जारी किए गए थे। जो कुल मिलाकर जीडीपी का 1.8 प्रतिशत हिस्सा बनते हैं। 2008-09 के दौरान विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती की राशि 13,371 करोड़ रुपए (तेल बांडों के लिए 13,349 करोड़ रुपए सहित) रही। इस चुकौती को हिसाब में लेते हुए मार्च 2009 की अंत की स्थिति के अनुसार बकाया विशेष प्रतिभूतियों की राशि 1,99,011 करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) रही।

राज्य सरकारों के वित्त : 2008-09

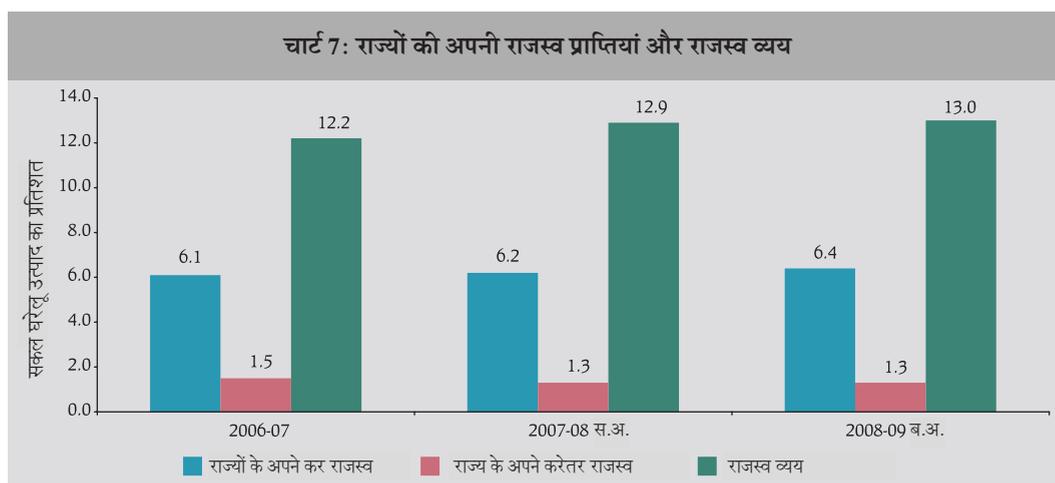
II.12 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है

ताकि वह जीडीपी के 0.54 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष दर्ज करे। राजस्व आधिक्य तथा ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों में बजट अनुमानों में वृद्धि को दर्शाते हुए समेकित स्तर पर जीएफडी-जीडीपी अनुपात 0.2 प्रतिशत अंक कम होकर 2.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है (देखें सारणी 11)। वर्ष 2008-09 के लिए राज्यों ने अपने बजट प्रस्तुत करते हुए अनेक नीतिगत पहलों की घोषणा की जिनका लक्ष्य राजस्व बढ़ाना और व्यय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की दिशा में मोड़ना है। अधिकांश राज्यों ने 2008-09 में कृषि और जल संरक्षण के लिए आबंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सभी राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए ऊंचे व्ययों का प्रस्ताव रखा। राज्य सरकारों ने सड़कों और शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए उंचे आबंटनों के साथ बुनियादी संरचना के विकास पर भी जोर दिया। कुछ राज्यों ने शहरी विकास और आवासन क्षेत्रों के लिए ऊंचे आबंटन प्रस्तावित किए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें इंदिरा आवास योजना और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शामिल हैं, निम्न और मध्यम आय समूहोंवाले परिवारों, झुग्गीवासियों और गरीबी की रेखा के नीचेवाले परिवारों के लिए मकान बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया है। बहुत-

सी राज्य सरकारों ने गरीबों के हितार्थ स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। कई राज्य सरकारों ने खजानों और कर विभागों का कंप्यूटरीकरण भी प्रस्तावित किया है।

II.13 2008-09 के दौरान बजट इस प्रकार बनाया गया था कि राज्य सरकार के समेकित राजस्व आधिक्य मूलतः राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि के माध्यम से बढ़े। 2008-09 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों के स्व-कर राजस्व और केंद्र से अधिक न्यागमन (डिवोल्यूशन) और अंतरणों के कारण दिखाई दी थी। जीडीपी से प्रतिशत के रूप में राज्यों के स्व-करेतर राजस्व का स्तर पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखना था (चार्ट 7)। 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि के बारे में अनुमान लगाया गया था कियह पिछले वर्ष के 19.9 प्रतिशत से घटकर 14.1 प्रतिशत पर आ जाएगी।

II.14 सभी राज्य सरकारों के समेकित सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन दर्शाता है कि पूंजी परिव्यय के बारे में अनुमान है कि यह लगातार तीसरे वर्ष भी 2008-09 (ब.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे से अधिक रहेगा जिसका वित्तपोषण मुख्य रूप से राजस्व लेखे के आधिक्य द्वारा किया जाना था। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के



प्रमुख स्रोत के रूप में बाजार उधारों के उभरने के साथ राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप में संरचनागत परिवर्तन हुआ। विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत हुआ करती थीं। अल्प बचतों के अंतर्गत संग्रह में तेज गिरावट की वजह से 2006-07 के लगभग तीन गुने की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों ने सकल राजकोषीय घाटे के दसवें हिस्से से भी कम का वित्तपोषण किया जबकि अनुमान था कि बाजार उधार सकल राजकोषीय घाटे के आधे से अधिक का वित्तपोषण करेंगे (सारणी 14)। तथापि, 2008-09 के दौरान हुई प्रगति ने दर्शाया कि

एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रह में लगातार कमी के चलते राज्य सरकारों को अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति दी गई थी जैसाकि 2007-08 में किया गया था। वर्ष 2008-09 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के वास्तविक बाजार उधारों का विवरण अध्याय-V में दिया गया है।

केंद्र सरकार के वित्त : 2009-10 के लिए बजट अनुमान

II.15 वर्ष 2009-10 के लिए केंद्र का अंतरिम बजट वैश्विक आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह आर्थिक मंदी नियंत्रित रखी जा सके। राजस्व संग्रहण के उछाल में गिरावट

सारणी 14 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का विनियोजन और पुनर्वित्त का स्वरूप

(प्रतिशत)			
मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4
विनियोजन (1+2+3+4)	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	-32.1	-20.9	-25.2
2. पूंजी परिव्यय	126.5	118.9	128.9
3. निवल ऋण	8.0	9.8	9.7
4. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	2.5	7.8	13.3
वित्तपोषण (1 से 11)			
1. बाजार उधार	16.9	58.9	56.7
2. केंद्र से ऋण	-11.5	3.2	6.2
3. एनएसएसएफ / अल्प बचतों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	72.3	8.8	19.6
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	5.1	6.8	6.5
5. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	13.4	11.3	11.5
6. आरक्षित निधि	9.8	-8.9	1.1
7. जमाराशियां और अग्रिम	16.5	4.7	4.3
8. उचंत और विविध	6.0	-4.5	-1.6
9. विप्रेषण	-0.4	-0.3	0.1
10. अन्य	-7.1	-2.2	-2.2
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-21.1	22.3	-2.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान एनएसएसएफ: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि
टिप्पणी: 1. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।
 2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
 3. वित्तपोषण की सभी मदें निवल आधार पर हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

का कारण न केवल आर्थिक मंदी रही बल्कि प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों में कर की दर में कटौती भी थी। वहीं व्यय भी काफी बढ़ा दिया गया था ताकि अर्थव्यवस्था में सकल मांग को प्रोत्साहन मिले।

II.16 हालांकि 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों पर पाया गया आर्थिक मंदी का विपरीत प्रभाव 2009-10 में बने रहने की आशा है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की संभावना भी रही है। तदनुसार, अनुमान लगाया गया कि 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 2008-09 (संशोधित अनुमान) के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो जाएंगी। 6.9 प्रतिशत पर सकल कर राजस्व की वृद्धि 2008-09 के 5.9 प्रतिशत की तुलना में अधिक रहेगी। तथापि जीडीपी के सापेक्ष सकल कर राजस्व में वर्ष के दौरान और गिरावट आएगी (सारणी 15)। अंतरिम बजट की घोषणा के पश्चात केंद्र सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (देखें अनुबंध 1) के एक अंग के रूप में अप्रत्यक्ष कर की दरों में और कमी करने की घोषणा की जिसका राजस्व वसूली पर असर पड़ेगा।

II.17 अनुमान है कि बीते वर्ष के दौरान सकल व्यय काफी बढ़ने के बाद 2009-10 में कम हो जाएगा (सारणी 16)। सकल व्यय में निम्न वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय से उत्पन्न होगी जिसके बारे में बजट में अनुमान लगाया गया है कि यह 2008-09 की 35.1 प्रतिशत की

वृद्धि से घटते हुए 5.6 प्रतिशत पर आ जाएगी। सब्सिडियों का नियंत्रण विशेष रूप से उर्वरक सब्सिडी का नियंत्रण 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय में धीमी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान कारक होगा। अनुमान है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जानेवाले अनुदानों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 14.7 प्रतिशत की तुलना में 10.4 प्रतिशत रहकर कम रहेगी। पूंजी व्यय, जिसमें पूंजी परिव्यय तथा अग्रिमों का समावेश रहता है, के बारे में भी अनुमान है कि यह 2008-09 की तुलना में 2009-10 में घटेगा (2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के हिस्से के अर्जन की लागत के लिए समायोजन करते हुए)। पूंजी परिव्यय के बारे में अनुमान है कि यह 16.7 प्रतिशत की वृद्धि (2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के हिस्से के अर्जन की लागत के लिए समायोजन करते हुए) की तुलना में 15.3 प्रतिशत बढ़ेगा। अनुमान है कि रक्षा पूंजी परिव्यय में 13,824 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और रक्षेतर पूंजी व्यय में 1,100 करोड़ रुपए की गिरावट आएगी।

II.18 वर्ष 2009-10 के लिए केंद्र के अंतरिम बजट में 2008-09 और 2009-10 के लिए एफआरबीएम लक्ष्यों में ढील के संकेत दिए गए हैं ताकि सकल मांग को प्रोत्साहन मिल सके। तथापि मध्यावधि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की दिशा में फिर से यथाशीघ्र वापस लौटने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। जीडीपी से प्रतिशत के रूप में महत्वपूर्ण घाटा संकेतक यथा राजस्व घाटा, जीएफडी और प्राथमिक घाटा 2009-10 में क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 4.4 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत कम रहेगा (देखें सारणी 11)।

II.19 2009-10 के दौरान निवल बाजार उधार (एमएसएस को घटाकर) 2008-09 के 2,66,539 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,08,647 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सकल

सारणी 15: केंद्र के सकल कर राजस्व

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)			
वर्ष	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1	2	3	4
2004-05	4.2	5.5	9.7
2005-06	4.4	5.8	10.2
2006-07	5.3	6.1	11.5
2007-08	6.3	6.3	12.6
2008-09 (सं.अ.)	6.4	5.2	11.6
2009-10 (ब.अ.)	6.3	4.8	11.1

सारणी 16 : केंद्र सरकार का 2009-10 का अंतरिम बजट - एक नजर में

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	
			2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	5,62,173 (10.4)	6,09,551 (10.1)	3.7	8.4
i) कर राजस्व (निवल)	4,65,970 (8.6)	4,97,596 (8.3)	6.0	6.8
ii) करेतर राजस्व	96,203 (1.8)	1,11,955 (1.9)	-6.0	16.4
2. योजनेतर व्यय	6,17,996 (11.4)	6,68,082 (11.1)	30.9 *	8.1
जिसमें से:				
i) ब्याज भुगतान	1,92,694 (3.6)	2,25,511 (3.7)	12.7	17.0
ii) रक्षा व्यय	1,14,600 (2.1)	1,41,703 (2.4)	25.0	23.7
iii) आर्थिक सहायता	1,29,243 (2.4)	1,00,932 (1.7)	82.2	-21.9
3. योजना व्यय	2,82,957 (5.2)	2,85,149 (4.7)	38.0	0.8
4. राजस्व व्यय	8,03,446 (14.8)	8,48,085 (14.1)	35.1	5.6
5. पूंजी व्यय	97,507 (1.8)	1,05,146 (1.7)	17.9 *	7.8
6. कुल व्यय	9,00,953 (16.6)	9,53,231 (15.8)	33.0 *	5.8
7. राजस्व घाटा	2,41,273 (4.4)	2,38,534 (4.0)	359.0	-1.1
8. सकल राजकोषीय घाटा	3,26,515 (6.0)	3,32,835 (5.5)	157.3	1.9
9. सकल प्राथमिक घाटा	1,33,821 (2.5)	1,07,324 (1.8)	-403.3	-19.8

* : 2007-08 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्टेट बैंक के स्टेक के अधिग्रहण लागत की ओर 35,531 करोड़ रुपए की राशि का समायोजन ।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

बाजार उधार (एमएसएस को घटाकर) जिसमें 93,087 करोड़ रुपए की चुकौती शामिल है, 2009-10 में 4,01,734 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जीएफडी के वित्तपोषण के अर्थ में निवल बाजार उधारों का हिस्सा (एमएसएस के अंतर्गत आबंटनों को छोड़कर), केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएफएफ द्वारा किए जानेवाले निवेश और बाह्य सहायता 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2009-10 में बढ़ने का अनुमान है। आरक्षित निधियों से बहिर्वाह 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2009-10 में कम रहने का अनुमान है। 2009-10 के दौरान बजट में यह आशा व्यक्त की गई है कि जीएफडी के वित्तपोषण के लिए नकद अधिशेष आहरित

नहीं किए जाएंगे जैसाकि 2008-09 (सं.अ.) में जीएफडी का 9.2 प्रतिशत आहरित किया गया (सारणी 17)।

कंपनी निष्पादन

II.20 वर्ष की पहली तिमाही के दौरान चुनिंदा वित्तेतर गैर सरकारी कंपनियों के कार्य निष्पादन के विश्लेषण ने दर्शाया कि 2007-08 की पहली छमाही की तुलना में बिक्री में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसा ऊंचे बिक्री मूल्यों और सतत ग्राहक मांग के कारण था। तथापि, बिक्री में वृद्धि की तुलना में व्यय में वृद्धि अधिक रही जिसका मूल कारण कच्चे माल की लागतों का बढ़ना जिसमें बिजली

**सारणी 17: सकल राजकोषीय घाटे के
वित्तपोषण का स्वरूप**

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
1	2	3
सकल राजकोषीय घाटा	3,26,515	3,32,835
निम्न द्वारा वित्तपोषित :		
बाजार उधार	2,66,539 (81.6)	3,08,647 (92.7)
अल्प बचत के विरुद्ध जारी प्रतिभूतियां	1,324 (0.4)	13,255 (4.0)
बाह्य सहायता	9,603 (2.9)	16,047 (4.8)
राज्य भविष्य निधि	4,800 (1.5)	5,000 (1.5)
एनएसएसएफ	11,206 (3.4)	1,022 (0.3)
आरक्षित निधि	-16,808 (-5.1)	-3,358 (-1.0)
जमा राशियां और अग्रिम	12,788 (3.9)	9,026 (2.7)
डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	2,594 (0.8)	2,672 (0.8)
नकदी आहरण	29,984 (9.2)	0 (0.0)
अन्य	4,486 (1.4)	-19,477 (-5.9)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

और ईंधन शामिल हैं, चुकाए जानेवाले ब्याज में वृद्धि और विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों को बाजार दर पर अंकित करने (एमटीएम) के संबंध में होनेवाली हानि के लिए भारी प्रावधान। इकट्टी हो रही इन्वेंटरी के भार और अन्य आय में गिरावट ने भी लाभप्रदता को प्रभावित किया जो 2008-09 की पहली छमाही के दौरान दबी रही थी।

II.21 2008-09 की तीसरी तिमाही के दौरान हालांकि मांग के कमजोर पड़ने से बिक्री में वृद्धि काफी घट गई थी। 2008-09 की पहली छमाही के दौरान विक्रेय माल के भरने की तुलना में तीसरी तिमाही में इन्वेंट्रियो के घटते जाने के माध्यम से आंशिक बिक्री हुई। हालांकि

इस अवधि के दौरान व्यय में वृद्धि में भी गिरावट आई लेकिन बिक्री की वृद्धि में गिरावट व्यय की वृद्धि की गिरावट की तुलना में ज्यादा तेज थी। परिणामस्वरूप सकल लाभ से बिक्री का अनुपात और बिक्री की तुलना में कर पश्चात लाभ के अनुपात के रूप में इन कंपनियों की मापी गई लाभप्रदता में गिरावट आई जो मार्जिनों पर दबाव को दर्शाती है। ब्याज भुगतानों में ऊंची वृद्धि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 2008-09 की तीसरी तिमाही में निवल लाभ में गिरावट के प्रमुख कारकों में से एक कारक थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते वर्ष में देखी गई भारी वृद्धियों की तुलना में तीसरी तिमाही के दौरान अन्य आय में गिरावट जारी रही (सारणी 18)।

II.22 विचितर सरकारी (तेल और तेल से इतर) कंपनियों ने पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 2008-09 की तीसरी तिमाही में राजस्व में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा निवल लाभ में 27.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। 2008-09 की तीसरी तिमाही में जहां तेल से इतर कंपनियों के निवल लाभ 10.3 प्रतिशत घटे वहीं तेल कंपनियों के लाभ में 45.4 प्रतिशत की तेज गिरावट आई। तीसरी तिमाही के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम के मूल्यों में हुई तेज कमी से इन्वेंट्रियो के मूल्यन से हानि और निर्यात से प्राप्त होनेवाला मूल्य भी कम रहा जिसने तेल कंपनियों के लाभों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इन कंपनियों के लाभ भारी ब्याज चुकौतियों और वेतन में संशोधन की प्रत्याशा में किए गए भारी प्रावधानों के कारण स्टाफ लागत में वृद्धि से भी प्रभावित हुए। तथापि 3 तेल विपणन कंपनियों ने इस तिमाही के दौरान 3,336 करोड़ रुपए के मिश्रित निवल लाभ दर्ज किए। उनके द्वारा कम वसूली (अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और मिट्टी के तेल के खुदरा मूल्यों में संशोधन न किए जाने के परिणामस्वरूप) से उठाए गए घाटे को

सारणी 18 : कंपनी क्षेत्र-वित्तीय कार्यनिष्पादन

(वृद्धि दरें / अनुपात प्रतिशत में)

मद	2007-08		2008-09	2007-08				2008-09		
	अप्रैल-दिसंबर			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिक्री	18.3	17.9	23.9	19.2	16.0	18.0	20.6	29.3	31.8	9.5
अन्य आय	46.2	68.0	-2.4	106.7	45.2	70.2	28.5	-8.4	-0.6	-4.8
व्यय	18.4	17.7	28.3	18.0	15.3	18.9	23.3	33.5	37.5	12.6
मूल्यहास प्रावधान	14.8	17.4	14.9	18.1	15.8	17.9	15.4	15.3	16.5	16.8
सकल लाभ	22.8	23.7	-1.7	31.9	22.5	20.4	16.8	11.9	8.7	-26.7
ब्याज भुगतान	28.8	25.1	65.4	44	18.4	45.7	35.8	58.1	85.3	62.9
करोत्तर लाभ	26.2	28.6	-16.7	33.9	22.7	29.4	14.1	6.9	-2.6	-53.4
चुनिंदा अनुपात										
बिक्री के प्रति सकल लाभ	16.3	16.0	13.1	16.7	16.3	16.2	15.0	14.5	13.5	11.0
बिक्री के प्रति करोत्तर लाभ	11.8	11.6	8.1	11.6	11.5	12.2	10.3	9.7	8.6	5.3
बिक्री के प्रति ब्याज	2.2	2.2	3.0	2.0	2.1	2.5	2.2	2.4	2.9	3.8
सकल लाभ के प्रति ब्याज	13.8	13.5	22.6	11.8	12.8	15.3	14.6	16.8	21.5	34.6
ब्याज की व्याप्ति (बार)	7.3	7.4	4.4	8.5	7.8	6.5	6.8	6.0	4.6	2.9
ज्ञापन:										
(राशि करोड़ रूप में)										
कंपनियों की संख्या	2,359	2,476	2,059	2,342	2,228	2,329	2,357	2,500	2,386	2,486
बिक्री	11,41,711	9,08,339	10,35,713	2,80,814	2,97,110	3,06,238	3,50,917	3,65,303	3,93,626	3,74,686
अन्य आय*	30,958	23,916	22,077	9,151	8,057	9,221	10,082	7,666	7,943	8,471
व्यय	9,56,930	7,63,735	8,97,759	2,37,698	2,49,194	2,57,472	3,02,105	3,17,605	3,43,921	3,22,077
मूल्यहास प्रावधान	40,664	32,075	34,191	10,173	10,576	10,961	11,805	11,590	12,075	14,563
सकल लाभ	1,86,665	1,45,492	1,35,541	46,780	48,296	49,717	52,583	52,930	52,968	41,299
ब्याज भुगतान	25,677	19,659	30,674	5,504	6,194	7,609	7,703	8,891	11,403	14,277
करोत्तर लाभ	1,34,291	1,05,686	83,664	32,699	34,266	37,470	36,109	35,295	33,844	19,962

*: अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है यदि स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए।

टिप्पणी: 1. आंकड़े चुनिंदा गैर - सरकारी गैर - वित्तीय सूचीबद्ध पब्लिक लिमि. कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।

2. वृद्धि दरें संदर्भाधीन अवधि के लिए कंपनियों के सामान्य सेट के लिए पिछले साल की तदनु रूप अवधि की तुलना में स्तर में प्रतिशत परिवर्तन हैं।

3. प्रत्येक अवधि में शामिल कंपनियों की संख्या और संरचना में अंतर होने के कारण हो सकता है कि पूरे साल के आंकड़े तिमाहियों के आंकड़ों के जोड़ से मेल न खाएं।

आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए तेल बांडों ने इन कंपनियों की निवल हानि को होने से बचा लिया।

बाह्य मांग

II.23 निवल बाह्य मांग, जैसीकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल निर्यात (माल और सेवाएं) में परिलक्षित है, पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के (-) 4.7 प्रतिशत

की तुलना में 2008-09 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान घटकर (-) 7.8 प्रतिशत हो गई। निर्यात और आयात (माल और सेवाएं) अप्रैल-दिसंबर 2007 में क्रमशः 23.3 प्रतिशत और 25.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2008 में क्रमशः 17.1 प्रतिशत और 27.3 प्रतिशत बढ़े। सितंबर 2008 से निर्यात की गति में कमी होने के साथ संबद्ध वर्ष के शुरुआती हिस्से में कच्चे तेल के ऊंचे मूल्यों के कारण वाणिज्यिक व्यापार घाटे

से जुड़ा हुआ था, ने ऊंची बचतों में अपना योगदान दिया। घरेलू बचत दर ने भौतिक बचत दर में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में मामूली सुधार दर्शाया (सारणी 19)। सकल देशी पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) की दर भी 2007-08 में जीडीपी का 39.1 प्रतिशत रही जोकि बहुत ऊंची है। 2007-08 के दौरान

बचत निवेश संतुलन ही चौड़ा हो गया जो बचत दर से आगे निवेश गतिविधि में सतत अचानक वृद्धि को दर्शाता है। तथापि यह नोट किया जा सकता है कि आर्थिक गतिविधि में मंदी आ जाने के कारण हो सकता है 2008-09 के दौरान बचत और निवेश में वृद्धि की यह स्थिर प्रवृत्ति बनी न रहे।

अनुबंध 1 : प्रमुख राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय

20 अक्टूबर 2008

- 2008-09 के केंद्रीय बजट में मुख्य रूप से स्कीमों/ योजनाओं के वित्तपोषण हेतु 1,05,613 करोड़ रुपए के निवल नकद बहिर्वाह के साथ सकल व्यय जिसकी राशि 2,35,286 करोड़ रुपए थी, के लिए सहायता अनुदान हेतु अनुपूरक मांग की घोषणा की गई लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए।

7 दिसंबर 2008

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 3 प्रमुख यथाअनुपात दरें अर्थात् 14 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत जो पेट्रोलियम उत्पादों से इतर उत्पादों पर लागू हैं प्रत्येक को 4 प्रतिशत घटा दिया गया।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रम प्रधान निर्यातों यथा टेक्सटाइल (हैंडलूम, गलीचे और दस्तकारी), चमड़ा, रत्न और आभूषण, सामुद्रिक उत्पाद के लिए पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण को लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए 31 मार्च 2009 तक 2 प्रतिशत की और ब्याज छूट प्रदान करके ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है बशर्ते ब्याज की न्यूनतम दर 7 प्रतिशत वार्षिक हो। टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी/ केंद्रीय बिक्री कर की पूरी धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए 1,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि की घोषणा की गई थी। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भी अलग से आबंटन घोषित किया गया था।
- योजना व्यय के माध्यम से प्रतिचक्रीय प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से चालू राजकोषीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त योजना व्यय आबंटित किया गया था।
- टेक्सटाइल क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना का पूरा बकाया (बैकलाग) निपटाने के लिए 1,400 करोड़ रुपए अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा।
- सरकारी निजी साझा पद्धति के अंतर्गत बुनियादी संरचना योजनाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंडिया

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) को 31 मार्च 2009 तक कर मुक्त बांडों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

19 दिसंबर 2008

- सकल व्यय के लिए प्रावधान किए गए अनुदानों हेतु द्वितीय अनुपूरक मांग की राशि 42,480 करोड़ रुपए के निवल नकद बहिर्वाह के साथ 55,605 करोड़ रुपए थी।

29 जनवरी 2009

- राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बदलकर 3.5 प्रतिशत करके वर्ष 2008-09 के लिए ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों में ढील दी गई ताकि पूंजी व्यय करने के लिए राज्य एकबारगी ढील के रूप में 2009-10 के दौरान अपने संबंधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक उधार ले सकें। इसके अलावा 2008-09 के लिए राजस्व घाटे को समाप्त करने की डीसीआरएफ अपेक्षा में भी ढील दी गई थी। 20 फरवरी 2009 को यह ढील वर्ष 2009-10 के लिए भी बढ़ा दी गई थी। राज्यों को डीसीआरएफ के लाभ का नुकसान नहीं होगा बशर्ते कि वे 2009-10 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल कर लें। राज्यों को आवश्यकतानुसार अपने संबंधित एफआरबीएम अधिनियमों को संशोधित करना होगा।

24 फरवरी 2009 (अंतरिमोत्तर बजट)

- उत्पाद शुल्क की दरों में 4 प्रतिशत अंक की की गई सामान्य कमी जो 7 दिसंबर 2008 से की गई थी उसे 31 मार्च 2009 से आगे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर भी 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था।